अपीलीय सिविल

समक्ष आरएस सरकारिया न्यायमूर्ति

हीरा और अन्य - *अपीलकर्ता* **1**

बनाम

बीर सिंह और अन्य - *प्रतिवादी*

1963 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 351

नवंबर 11, 1967

पंजाब प्री-एम्प्शन अधिनियम (1913 का 1) अधिनियम *(1960 का X) द्वारा संशोधित* - धारायें 13, 15(1)(बी) *दूसरे और* 17- प्रीएम्प्शन *का अधिकार - चाहे निर्दिष्ट रिश्तेदारों में निहित हो या उत्तराधिकारियों की पूरी पंक्ति में - भाई और भाई के बेटों में - क्या समान और स्वतंत्र अधिकार हैं* - धारा 15 के विभिन्न खंडों में *"या" शब्द*

अभिनिर्धारित कि, 1960 के पंजाब अधिनियम 10 ने पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट, 1913 में संशोधन करते हुए, प्री-एम्प्शन के अधिकार को छीनकर गाँव की अचल संपत्ति और कृषि भूमि के संबंध में प्री-एम्प्शन के कानून के आधार को पूरी तरह से बदल दिया है। पूर्व में उत्तराधिकारियों की पूरी श्रृंखला में निहित, तथापि, दूरस्थ और कुछ निर्दिष्ट रिश्तेदारों को यह अधिकार दे दिया गया है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 15(1)(बी), दूसरे में उल्लिखित विक्रेता के भाई और भाई के बेटों को पूर्व-भुगतान का समान और स्वतंत्र अधिकार है, न कि उत्तराधिकारियों के माध्यम से।

अभिनिर्धारित कि पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट के विभिन्न प्रावधानों को एक-दूसरे के साथ टकराव के बजाय सामंजस्य में समझा जाना चाहिए। यदि धारा 13 को निरर्थक नहीं बनाया जाना है और धारा 17 धारा 15 के विभिन्न खंडों में 'या' शब्द को हटा देती है, तो इसे केवल समन्वय स्थिति या पूर्व-मुक्ति के समान अधिकार वाले व्यक्तियों के लिए एक कनेक्टिंग शब्द के रूप में समझा जाना चाहिए। इसे एक वैकल्पिक, विघटनकारी शब्द के रूप में केवल इस अर्थ में पढ़ा जा सकता है कि किसी विशेष खंड में उल्लिखित समन्वित अधिकारों वाले इन व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या उसी खंड में अन्य लोगों के साथ संयुक्त रूप से पूर्व के लिए मुकदमा दायर कर सकता है।

वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, हिसार के न्यायालय के दिनांक 17 अक्टूबर, 1962 के आदेश से दूसरी अपील *, उप-न्यायाधीश,* प्रथम *श्रेणी, हिसार के दिनांक* 11 *फरवरी,* 1960 के फैसले की पुष्टि करते हुए। *वादी के पक्ष में और प्रतिद्वंद्वी वादी के पक्ष में, प्रीएम्प्शन के माध्यम से, वाद भूमि के आधे हिस्से के कब्जे के लिए एक डिक्री प्रदान करना और आगे यह आदेश देना*

कि प्रीएम्प्शन करने वालों के दोनों समूह 31 *मार्च,* 1960 *तक राशि जमा* करेंगे *, अन्यथा उनके मुकदमे खारिज कर दिये जायेंगे।*

अपीलकर्ता के लिए:- जीसी मित्तल, अधिवक्ता।

2

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए:- आरसी डोगरा, अधिवक्ता।

<u>निर्णय</u>

आरएस सरकारिया, न्यायमूर्ति - निम्नलिखित वंशावली 1963 की इस नियमित द्वितीय अपील संख्या 351 को जन्म देने वाले तथ्यों को समझने में सहायक होगी: -

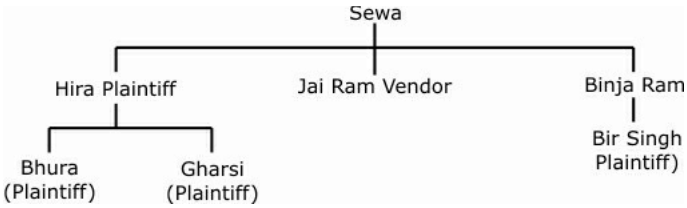

जय राम (उपरोक्त वंशावली तालिका में दिखाया गया है) ने, सरसाना गांव, तहसील हिसार के क्षेत्र में स्थित 633 कनाल और 10 मरला कृषि भूमि में अपना ⅓rd हिस्सा 5,000 रुपये में बेच दिया। एक पंजीकृत विलेख द्वारा, 5 जुलाई, 1957 को निष्पादित , लेकिन 1 मार्च, 1958 को पंजीकृत किया गया। बिंजा राम के पुत्र बीर सिंह ने 9 मई, 1959 को बिक्री को पूर्व-खाली करने के लिए मुकदमा संख्या 125 स्थापित किया। इस आधार पर कि वह विक्रेता के भाई का बेटा था। प्री-एम्प्शन के लिए एक और मुकदमा विक्रेता के भाई हीरा लाल और उनके बेटों, भूरा और घारसी द्वारा पंजाब प्री-एम्पशन अधिनियम 1913 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 15 (1) (बी) के दूसरे खंड के प्रावधानों पर अपना दावा करते हुए दायर किया गया था। ट्रायल नयायालय (सबजज, प्रथम श्रेणी, हिसार) ने मुकदमे पर फैसला सुनाया कि बीर सिंह वादी आधे हिस्से का हकदार था, जबकि हीरा और उसके बेटे, घरसी और भूरा संपत्ति के शेष आधे हिस्से के हकदार थे। हीरा और उसके बेटों ने वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, हिसार के पास अपील की और दावा किया कि प्रत्येक वादी-पूर्व-खालीकर्ता मुकदमे की संपत्ति के चौथाई हिस्से का हकदार था। वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश ने अपने गूढ़ निर्णय से अपील को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि की। हीरा और उसके बेटे इस अदालत में दूसरी अपील लेकर आए हैं।

15(1)(बी) के दूसरे खंड में उल्लिखित "विक्रेता के भाई या भाई के बेटे" को प्री-एम्प्शन का समान और स्वतंत्र अधिकार दिया गया है। वकील के अनुसार, यह पिछले अधिनियम के पुनर्निर्माण और 1960 के संशोधन द्वारा 'उत्तराधिकार के क्रम में' शब्दों को हटाने का प्रभाव है। विद्वान वकील धारा 13 के प्रावधानों से भी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं । जो कहते हैं:

“जब कभी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पूर्व-अनुभव का अधिकार किसी वर्ग या व्यक्तियों के समूह में निहित होता है, तो इस अधिकार का प्रयोग ऐसे वर्ग या समूह के सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा सकता है, और यदि उन सभी द्वारा संयुक्त रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उनमें से किन्हीं दो या अधिक द्वारा संयुक्त रूप$_3$से, और, यदि उनमें से किन्हीं दो या अधिक द्वारा संयुक्त रूप से उनके द्वारा अलग-अलग प्रयोग नहीं किया जाता है, "

विद्वान वकील ने 1960 के आरएसए 1615 में इस न्यायालय के एकल पीठ के फैसले का हवाला दिया है , जो 20 मार्च, 1962 को गुरदेव सिंह, न्यायमूर्ति द्वारा तय किया गया था , जिसकी पुष्टि एक डिवीजन बेंच द्वारा लेटर्स पेटेंट अपील में की गई थी। जिसमें दुलत और आरपी खोसला, न्यायमूर्ति शामिल हैं। यह भी आग्रह किया गया है कि जहां तक प्रतिद्वंद्वी पूर्व-खालीदारों के बीच संपत्ति के वितरण का सवाल है, मामला अधिनियम की धारा 17 के अवशिष्ट खंड (ई) के तहत आएगा , न कि इसके खंड (बी) के तहत। तर्क यह है कि अधिनियम के तहत, 1960 के संशोधन के बाद , पूर्व-मुक्ति का अधिकार निर्दिष्ट व्यक्तियों को दिया गया है, न कि उत्तराधिकारियों की पूरी श्रृंखला को, और यह कि ग्राम समुदाय की सघनता बनाए रखने की पुरानी अवधारणा पर आधारित है उत्तराधिकार के एग्मैटिक सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में, यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में "भाई और भाई के बेटे" 'उत्तराधिकारी' के रूप में दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल एक समूह में निर्दिष्ट व्यक्तियों के रूप में दावा कर रहे हैं जिनके पास पूर्व-मुक्ति का समान और स्वतंत्र अधिकार है। यह तर्क दिया जाता है कि धारा 17 का ऐसा अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि धारा 15 द्वारा दिए गए मूल अधिकार को पूरी तरह से छीन लिया जाए। इस बिंदु पर **फ़तेह मोहम्मद और अन्य बनाम फ़तेह मोहम्मद, 1947 पीएलआर 160** पर निर्भरता रखी गई है ।

वहीं दूसरी ओर श्री डोगरा, प्रतिद्वंद्वी प्री-एम्प्टर, बीर सिंह के विद्वान वकील, का तर्क है कि घरसी और भूरा वादी के पास प्री-एम्प्शन का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन वे केवल अपने पिता, हीरा के माध्यम से दावा कर सकते थे, जिनके बेटों के पास उनके पिता के मुकाबले अधिमान्य अधिकार था। यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रतिनिधित्व का सिद्धांत उनके मामले पर लागू होगा। यह स्पष्ट रूप से सुझाव दिया गया है कि अधिनियम की धारा 15(1)(बी) के खंड 'द्वितीय' में 'या' शब्द का अर्थ है कि या तो 'भाई' (हीरा) या उसके 'बेटों' (घारसी और भूरा) को अधिकार था पूर्व-मुक्ति का, और, एक साथ, उन दोनों को वह अधिकार नहीं मिल सकता था। लेकिन जहां तक बीर सिंह का सवाल है, वकील कहते हैं, यह सच नहीं है क्योंकि उनके पिता, बिंजा, वादी नहीं हैं और उनके चाचा, हीरा, उक्त धारा के तहत उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। वकील के अनुसार, बीर सिंह के पास पूर्व-मुक्ति का स्वतंत्र और समान अधिकार था क्योंकि वह अपने पिता बिंजा के साथ और उसके माध्यम से दावा नहीं कर रहा है। संक्षेप में, श्री डोगरा का कहना है कि प्रतिद्वंद्वी पूर्व-खालीदारों के बीच मुकदमे की संपत्ति का वितरण per stripes होना चाहिए ना कि per capita.

मैंने इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था क्योंकि **जंगली और अन्य बनाम लखमी चंद और अन्य, 1965 पीएलआर 919** में लेटर्स पेटेंट बेंच द्वारा निर्धारित नियम पर पूर्ण समिति द्वारा पुनर्विचार किया जा रहा था। **मोती राम बनाम बखवंत सिंह, 1964 के एलपीए 340, आईएलआर (1968) 1 पंजाब 104** में पूर्ण पीठ का निर्णय 29 सितंबर, 1967 को सुनाया गया था और जंगली के मामले के अनुपात को खारिज कर दिया गया था। फलशॉ और खन्ना, न्यायमूर्ति की संदर्भित पीठ द्वारा इस आशय का दृष्टिकोण अपनाया गया है कि धारा 13 का उद्देश्य सर्वोच्चता का कोई अधिकार प्रदान करना नहीं है और इसका अर्थ यह है कि व्यक्तियों के समूह में से एक, जिसे पूर्व-अनुभव का अधिकार प्रदान किया गया है, अकेले उस अधिकार का उपयोग कर सकता है जब अन्य ऐसा करने के इच्छुक नहीं हैं। लेकिन वह संयुक्त मालिकों द्वारा बेची गई पूरी भूमि के संबंध में केवल तभी ऐसा कर सकता है जब उसे प्रत्येक 'विक्रेताओं' के संबंध में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हो। **1964 के एलपीए 340, मोती राम और अन्य बनाम बखवंत सिंह और अन्य (सुप्रा)** में पूर्ण पीठ का निर्णय मेरे सामने मामले के उद्देश्य के लिए सामग्री है। पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित अन्य बिंदु तत्काल मामले में नहीं उठते हैं।

यहां, निर्धारण के बिंदु अधिनियम की धारा 13 , धारा 15(1)(बी) द्वितीय और धारा 17 की व्याख्या से संबंधित हैं। पहला सवाल यह है कि क्या धारा 13 और 17 के साथ पढ़ा जाने वाला यह खंड भाई और भाई के बेटों को बिक्री के संबंध में पूर्व-मुक्ति का समान और स्वतंत्र अधिकार प्रदान करता है। इस प्रश्न का निर्धारण काफी हद तक धारा 15 के विभिन्न खंडों में प्रयुक्त 'या' शब्द के वास्तविक अर्थ पर निर्भर करता है। पहली नजर में, 'या' शब्द के उपयोग के परिणामस्वरूप विभिन्न विकल्प बनते प्रतीत होते हैं और किसी विशेष खंड के तहत समूहीकृत व्यक्तियों के बीच अधिमान्य क्रम के निर्धारण में भी। मामले को ध्यान में रखते हुए, भाई के पास विक्रेता के भाई के बेटों पर प्री-एम्प्शन का अधिमान्य अधिकार होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि, भाई के पुत्रों का पूर्वाधिकार का अधिकार तभी उत्पन्न होगा जब भाई उस अधिकार का प्रयोग नहीं करता है। मेरे विचार में, इस तरह की व्याख्या न केवल धारा 13 के प्रावधानों को निरर्थक बना देगी, बल्कि धारा 17 को भी पूरी तरह से निरर्थक बना देगी । इसलिए, यह सही दृष्टिकोण नहीं प्रतीत होता है। मैक्सवेल कहते हैं, "एक लेखक को स्वयं के अनुरूप होना चाहिए, और इसलिए, यदि एक स्थान पर वह अपने मन को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है, तो यह माना जाना चाहिए कि वह दूसरे स्थान पर भी उसी मन का है जब तक कि वह स्पष्ट रूप से न हो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इसे बदल दिया है। विधायिका के कार्य को किसी अन्य लेखक के कार्य के समान ही माना जाता है।" इसलिए, अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को एक-दूसरे के साथ टकराव के बजाय सद्भाव में समझा जाना चाहिए। यदि धारा 13 को अर्थहीन नहीं बनाया जाना है और धारा 17 को हटा दिया जाना है, तो धारा 15 के विभिन्न खंडों में 'या' शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसे केवल समन्वय स्थिति या छूट के समान अधिकार वाले व्यक्तियों के लिए एक कनेक्टिंग शब्द के रूप में समझा जाना चाहिए। इसे एक वैकल्पिक, विघटनकारी शब्द के रूप में केवल इस अर्थ में पढ़ा जा सकता है कि उन व्यक्तियों के बीच में उल्लिखित समन्वय अधिकार हैं एक विशेष खंड, कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त

रूप से उसी खंड में अन्य लोगों के साथ (धारा 13 के मद्देनजर) प्री-एम्प्शन के लिए मुकदमा दायर कर सकता है।

मुद्दे को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, इस अधिनियम के इतिहास पर एक संक्षिप्त नज़र डालना सार्थक होगा। कृषि भूमि और गांव की अचल संपत्ति के संबंध में,[5] पंजाब में प्री-एम्प्शन ने पैतृक उत्तराधिकारियों को परिवार में संपत्ति बनाए रखने में सक्षम बनाया और इस प्रकार अजनबियों को छोड़कर गांव समुदाय की अखंडता और एकरूपता को संरक्षित किया। इस प्रकार यह भूमि में उत्तराधिकार के जनजातीय कानून की एक शाखा थी, और इसकी उत्पत्ति उत्तराधिकार के अज्ञेयवादी सिद्धांत में पाई जाती है। पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट, 1913 , पूर्व-एम्प्शन का दावा करने के लिए रिश्तेदारों के अधिकारों को मान्यता देता है (संबंधित कृषि भूमि और गाँव की अचल संपत्ति के लिए) पंजाब कानून अधिनियम की तुलना में अधिक उदारतापूर्वक। 1913 के अधिनियम की धारा 15 का भौतिक भाग इस प्रकार है:

"15 .... कृषि भूमि और गांव की अचल संपत्ति के संबंध में प्रीएम्प्शन का अधिकार निहित होगा -

(ए) जहां बिक्री एकमात्र मालिक या अधिभोग किरायेदार द्वारा की जाती है या, संयुक्त रूप से स्वामित्व या धारण की गई भूमि या संपत्ति के मामले में, सभी सह-हिस्सेदारों द्वारा संयुक्त रूप से, उत्तराधिकार के क्रम में, विक्रेता या विक्रेताओं की मृत्यु के क्रम में, बेची गई भूमि या संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने के लिए;

(बी) जहां बिक्री संयुक्त भूमि या संपत्ति में से एक हिस्से की है, और सभी सहभागियों द्वारा संयुक्त रूप से नहीं की जाती है,

सबसे पहले, उत्तराधिकार के क्रम में विक्रेता के वंशजों में;

दूसरे, सह-हिस्सेदारों में, यदि कोई हो, जो उत्तराधिकार के क्रम में ऐग्नेट हैं;

तीसरा, उत्तराधिकार के क्रम में ऊपर पहले या दूसरे में शामिल नहीं किए गए व्यक्तियों में, जो ऐसी बिक्री के अलावा, विक्रेता की मृत्यु पर, बेची गई भूमि या संपत्ति को विरासत में पाने के हकदार होंगे;

चौथा, सह-हिस्सेदारों में:"

पुरानी धारा 15 का उद्देश्य गाँव के पारिवारिक आधार को सुरक्षित करना था, और जब वह विफल हो गया, तो गाँव की अखंडता को बनाए रखना था। व्यापक सिद्धांत यह था कि कानूनी उत्तराधिकारी पहले आते थे, फिर सह-हिस्सेदार, फिर गाँव के मालिक और अंत में अधिभोगी किरायेदार आते थे। प्रत्येक समूह के भीतर, उत्तराधिकार में निकटतम ने अधिक दूरस्थ को बाहर कर दिया। यह पुरानी धारा 15 के खंड (ए) और (बी) में आने वाले 'उत्तराधिकार के क्रम में'

वाक्यांश का आयात था , जो उत्तराधिकारियों की पूरी पंक्ति पर प्री-एम्प्शन का अधिकार प्रदान करता था, न कि केवल निकटतम अनुमानित वारिस पर। 1960 के संशोधन अधिनियम 10 ने पुराने खंड को फिर से तैयार किया, उत्तराधिकार के क्रम में शब्दों को हटा दिया, कुछ निर्दिष्ट रिश्तेदारों के लिए रक्त-संबंध के आधार पर पूर्व-खाली की लड़ाई को सीमित कर दिया और भूमि सुधार देने वाले किरायेदारों के एक उपाय के रूप में एक नई सुविधा पेश की। उनकी किरायेदारी

में शामिल भूमि के संबंध में पूर्व-खाली का अधिकार। संशोधन अधिनियम ने पुरानी धारा 13 को अछूता छोड़ दिया , धारा 15 को पुनर्गठित किया (जैसा कि 1964 के पंजाब अधिनियम संख्या 13 द्वारा संशोधित किया गया है), उप-खंड (1) में , खंड पहले, दूसरे और तीसरे, केवल कुछ निकटतम को वर्गीकृत किया गया है रिश्तेदार जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विक्रेताओं के उत्तराधिकारी होंगे, पहले खंड के तहत 'विक्रेता' का बेटा या बेटी या बेटे का बेटा या बेटी का बेटा आता है। खंड 'दूसरे' के अंतर्गत 'विक्रेता का भाई या भाई का पुत्र' आता है। खंड तीसरे में 'विक्रेता के पिता के भाई या पिता के भाई के पुत्र' का उल्लेख किया गया है। खंड चौथा किरायेदारों से संबंधित है। खंड पहले में उल्लिखित व्यक्तियों को खंड दूसरे में उल्लिखित लोगों पर प्राथमिकता होगी, और इसी तरह खंड दूसरे में निर्दिष्ट लोगों को खंड तीसरे में उल्लिखित लोगों के मुकाबले अधिमान्य अधिकार होगा।

एक खंड में व्यक्तियों के बीच अगले खंड के ऊपर निर्धारित अधिमान्य क्रम और साथ ही एक विशेष खंड में रिश्तेदारों के नामों की व्यवस्था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा निर्धारित उत्तराधिकारियों के बीच उत्तराधिकार के क्रम के अनुसार सख्ती से नहीं है। उदाहरण के लिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बिना वसीयत के मरने वाले पुरुष हिंदू की संपत्ति, धारा 8 (वर्ग II) के तहत संलग्न अनुसूची के अनुसार , पहले पिता को जाती है; फिर बेटे की बेटी का बेटा, बेटे की बेटी की बेटी, भाई और बहन को। इसके बाद वर्ग II के अंतर्गत प्रविष्टि क्रमांक 3 है जिसमें सजातीयों की चार श्रेणियों का उल्लेख है। 'भाई का बेटा' 6 सजातीयों के बाद आता है और उसका नाम कक्षा II के अंतर्गत प्रविष्टि संख्या 4 में उल्लेखित है । प्री-एम्प्शन एक्ट पिता और प्रविष्टि संख्या 2 में उल्लिखित उत्तराधिकारियों की पहली दो श्रेणियों को हटा देता है। इसमें भाई का उल्लेख है और उसके बाद प्रविष्टि संख्या 3 में सभी सजातीय उत्तराधिकारियों को हटा दिया गया है , और फिर भाई के बेटे का उल्लेख है।

संशोधित अधिनियम ने धारा 17 के खंड (सी) और (डी) को हटा दिया है, जबकि खंड (ए) (बी) और (ई) को पहले की तरह रहने की अनुमति दी गई है।

इस मामले में कठिनाई धारा 17 के उचित अनुप्रयोग के संबंध में उत्पन्न होती है। कुछ हद तक, यह कठिनाई विभिन्न पंजाब अधिनियमों द्वारा किए गए टुकड़ों में संशोधनों का परिणाम है। जबकि 1960 के पंजाब अधिनियम ने, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, पूर्व-मुक्ति के अधिकार को छीनकर गांव की अचल संपत्ति और कृषि भूमि के संबंध में छूट के कानून के आधार को पूरी तरह से बदल दिया है, जो पहले उत्तराधिकारियों की पूरी श्रृंखला में निहित था, चाहे वह कितना भी दूर क्यों न हो। और कुछ निर्दिष्ट रिश्तेदारों को यह अधिकार दिया गया है, यह धारा

17 के खंड (बी) में 'यदि वे उत्तराधिकारी के रूप में दावा करते हैं', पुरानी कालानुक्रमिक वाक्यांशविज्ञान को बरकरार रखता है । अधिक सटीक होने के लिए, यदि वर्तमान मामले में भाई (हीरा) और विक्रेता के भाई के बेटे भूरा, घरसी और बीर सिंह वादी को 'उत्तराधिकारी के रूप में' प्रीएम्प्शन का दावा करने वाला माना जाता है, तो प्रथम दृष्टया धारा 17 का खंड (बी) मामले को नियंत्रित करने के लिए प्रतीत होता है, और, उस स्थिति में , मुकदमे की पूरी ज़मीन भाई, हीरा-वादी को मिलेगी, और अन्य तीन वादी को नहीं, जो विक्रेता के भाई के बेटे हैं। इस तरह की व्याख्या एक हाथ से अधिकार देने (अर्थात धारा 15 और 13) और दूसरे हाथ से छीनने के समान होगी। इस बिंदु पर कोई प्रत्यक्ष अधिकार नहीं है कि नई धारा 15(1) में खंड पहले, दूसरे और तीसरे के तहत निर्दिष्ट रिश्तेदारों के रूप में दावा करने वाले प्रतिद्वंद्वी पूर्व-खालीदारों के बीच भूमि कैसे वितरित की जाएगी। लेकिन पुराने अधिनियम के तहत एक समान मुद्दा लाहौर उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के समक्ष निर्धारण के लिए आया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश अब्दुल रशीद और श्री न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन शामिल थे। उस मामले में **फ़तेह मोहम्मद और अन्य बनाम फ़तेह मोहम्मद** , एक ही बिक्री के संबंध में प्रतिद्वंद्वी प्री-एम्प्टर्स द्वारा दो मुकदमों की कोशिश की गई थी। पहला मुकदमा इब्राहिम के बेटे फतेह मोहम्मद द्वारा दायर किया गया था, जिसने इस आधार पर अधिकार का दावा किया था कि वह विक्रेता का संपार्श्विक था और वह उस पट्टी का मालिक था जिसमें भूमि स्थित थी। दूसरा मुकदमा कालू और सरदार अली के बेटे फतेह मोहम्मद द्वारा दायर किया गया था। उन्होंने खाते में सह-हिस्सेदार होने और उस पट्टी में मालिक होने के आधार पर दावा किया जिसमें भूमि स्थित थी। ट्रायल न्यायाधीश ने माना कि दोनों मुकदमों में वादी के पास पट्टी के मालिक होने के आधार पर समान पूर्वव्यापी अधिकार थे, और दोनों मुकदमों को प्रत्येक भूमि के आधे-आधे हिस्से की सीमा तक डिक्री कर दिया। इब्राहिम के बेटे फतेह मोहम्मद ने उस फैसले के खिलाफ अपील की। उनकी अपील स्वीकार कर ली गई और पूरी जमीन की डिक्री उनके पक्ष में पारित कर दी गई। कालू और सरदार अली के बेटे मोहम्मद ने हाईकोर्ट में दो दूसरी अपीलें दायर कीं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने निचली अपीलीय अदालत के आदेश को बरकरार रखा और दोनों अपीलों को खारिज कर दिया। फैसले के खिलाफ, दो पत्र पेटेंट अपीलें दायर की गईं, उन अपीलों को स्वीकार करते हुए, महाजन, न्यायमूर्ति ने डिवीजन बेंच का फैसला सुनाते हुए कहा: -

"... अधिनियम की धारा 17(ई) की व्याख्या इस तरीके से की जानी चाहिए जो इसे धारा के शुरुआती शब्दों के साथ-साथ धारा 15(बी) के अनुरूप बनाए। चौथा, दूसरे शब्दों में जब दो प्री-एम्प्टर्स को प्री-एम्प्शन का समान अधिकार है तो धारा 17 पर रखा गया निर्माण ऐसा होना चाहिए जो एक या दूसरे के अधिकार को नष्ट न करे। मेरे निर्णय में, धारा 17 का खंड (सी) केवल मामलों पर लागू होता है जहां दो शर्तें पूरी होती हैं, यानी, (1) जहां प्री-एम्प्टर्स के दोनों सेट एक उप-विभाजन में मालिक हैं, और (2) जहां वे दोनों एक निश्चित अनुपात में शमिलत में हिस्सा लेने के हकदार हैं। खंड, हालाँकि, इसका कोई अनुप्रयोग नहीं है जहाँ प्री-एम्प्टर्स का एक सेट दूसरे सेट के साथ किसी भी अनुपात में शामिलाट को साझा करने का हकदार नहीं है। दूसरे शब्दों में, जब प्री-एम्प्टर्स के दोनों सेटों के बीच कुछ निश्चित अनुपात में शमिलत को

विभाजित किया जाता है, तो यह खंड को उचित रूप से लागू किया जा सकता है। लेकिन जहां किसी व्यक्ति के पास शून्य शेयर है या बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है और इसलिए, वह इसे अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ किसी भी अनुपात में साझा करने का हकदार नहीं है, इन परिस्थितियों में, इस खंड का कोई अनुप्रयोग नहीं रह जाता है । एकमात्र अन्य खंड जो ऐसे मामले को नियंत्रित कर सकता है वह अनुभाग का खंड (ई) है। यह अवशिष्ट उपवाक्य की प्रकृति में है। धारा 17 के मूल सिद्धांत का उल्लेख इसके शुरुआती शब्दों में किया गया है और खंड (ई) में कहा गया है कि आम तौर पर समान पूर्व-खाली अधिकार रखने वाले प्रतिद्वंद्वी पूर्व-खाली अधिकार समान रूप से साझा करेंगे जब तक कि मामला खंड (ए) से (डी) में से किसी एक के अंतर्गत नहीं आता है। मैं जो विचार रख रहा हूं वह धारा 17 के खंड (बी) के शब्दों से भी समर्थित है। यह खंड प्रतिद्वंद्वी उत्तराधिकारियों के दावे से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल भी उत्तराधिकारी नहीं है और वह शून्य शेयर का हकदार होने पर भी उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है, तो ऐसे मामले में खंड (डी) लागू नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, किसी मान्यता प्राप्त उपखंड में शामिलाट में शून्य हिस्सेदारी वाला मालिक इसे अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ किसी भी अनुपात में साझा करने का हकदार नहीं है, और उसका मामला उस खंड के दायरे में नहीं आ सकता है। एक बार धारा 15 के तहत उसका अधिकार स्वीकार कर लिया गया , तो अधिकार के प्रयोग से संबंधित धारा उसे पराजित नहीं कर सकती।"

यद्यपि अधिनियम के बाद के संशोधनों द्वारा, धारा 15 और 17 के प्रावधान , जो उस मामले में विद्वान न्यायाधीशों के विचाराधीन थे, या तो हटा दिए गए हैं या काफी हद तक संशोधित किए गए हैं, फिर भी धारा 15 और 17 की व्याख्या का सिद्धांत फ़तेह में निर्धारित किया गया है और मामला कायम है। उस सिद्धांत का सम्मानपूर्वक पालन करते हुए, मैं कहूंगा कि वर्तमान मामला अवशिष्ट खंड (ई) के अंतर्गत आता है, न कि धारा 17 के खंड (बी) के अंतर्गत । कारण, जैसा कि पहले ही देखा गया है, दो प्रकार के हैं: सबसे पहले, कोई भी अन्य व्याख्या धारा 15(1)(बी) द्वारा विक्रेता के भाई के बेटे को दिया गया प्री-एम्प्शन के समान अधिकार को नष्ट कर देगी। , और धारा 13 को भी अर्थहीन बना देगी । दूसरे, धारा 15(1)(बी) के पहले तीन खंडों के तहत पूर्व-मुक्ति का अधिकार कुछ निर्दिष्ट रिश्तेदारों को दिया गया है, न कि "उत्तराधिकारियों" को। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि वादी धारा 17 के खंड (बी) के चिंतन के तहत "उत्तराधिकारी के रूप में दावा करते हैं"।

उपरोक्त कारणों से मैं इस अपील को यह मानते हुए कि लागत के साथ स्वीकार करूंगा कि चार प्रतिद्वंद्वी वादी प्रीमेप्टर अधिनियम की धारा 17 के खंड (ई) के तहत मुकदमे की भूमि को समान शेयरों में साझा करेंगे।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया

जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

उदित अग्रवाल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा